

रजिस्टर्ड नं० ल०-33/13-14/93



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शनिवार, 6 फरवरी, 1993/17 माघ, 1914

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग  
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-171002, 4 जनवरी, 1993

संख्या एल०एल०आर० (राजभाषा) बी (16)-13/92.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक-उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश अरवन इस्टेट (डिवेलपमेण्ट एण्ड रेग्युलेशन) ऐक्ट, 1968 (1969 का 26)" के, संलग्न

अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

**हिमाचल प्रदेश नगरीय सम्पदा (विकास और विनियमन)  
अधिनियम, 1968**

(1969 का 26)

(30-9-1992 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में नगरीय सम्पदा के विकास और विनियमन के सम्बन्ध में विधि अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश नगरीय सम्पदा (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1968 है। संक्षिप्त नाम,  
विस्तार  
और प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) “विज्ञापन” से पूर्णतः या अंशतः विज्ञापन आख्यापन या निर्देशन के लिए आशयित कोई शब्द, अक्षर, प्रतिमान, संकेत, प्लेकार्ड, बोर्ड, नोटिस, आकृति या किसी रीति में चाह जो भी हो, रूपण अभिप्रेत है और विज्ञापनों के संप्रदर्शन के लिए प्रयुक्त या अनुकूलित, कोई संरचना इसके अन्तर्गत है ;

(ख) “मुख्य सुविधा” के अन्तर्गत, सड़क, जल प्रदाय, मार्ग प्रकाश, जल निकास, मल बहन, लोक इमारत, बागवानी, भू-दृश्य और नगरीय सम्पदा में प्रदान की गई कोई अन्य लोक उपयोगी सेवा है ;

(ग) “इमारत” से धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विक्रीत, पट्टे पर दिया गया या अन्तर्गत किता गया कोई निर्माण या निर्माण का भाग अभिप्रेत है और जो आवासिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के प्रयोग के लिए आशयित है, चाहे वास्तविक उपयोग में हो या नहीं, और कोई उपग्रह, अस्तबल, पशुशाला और गैराज इसके अन्तर्गत है और राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन विक्रीत, पट्टे पर दी गई या अन्तर्गत किसी भूमि पर परिनिर्मित कोई इमारत भी इसके अन्तर्गत है ;

(घ) “मुख्य प्रशासक” से इस अधिनियम के अधीन एक या एक से अधिक नगरीय सम्पदा के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक के कृत्यों के पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा, इस रूप में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) “इमारत का परिनिर्माण करना” का वही अर्थ है, जो हिमाचल प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1968 में “किसी इमारत का परिनिर्माण करना या पुनः परिनिर्माण करना” अभिव्यक्ति का है ;

- (च) "सम्पदा अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन एक या एक से अधिक नगरीय सम्पदा में, सम्पदा अधिकारी के कृत्यों के पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (छ) "अधिभोगी" से किसी फर्म या अन्य व्यक्ति-निकाय सहित, चाहे वह निगमित है या नहीं, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति में विक्रीत, पट्टे पर दी गई, या अन्तरित किसी स्थल या इमारत का अधिभोग करता है, और उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी इस के अन्तर्गत हैं ;
- (ज) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है ;
- (झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ञ) "स्थल" से कोई भूमि अभिप्रेत है, जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अन्तरित की जाती है ;
- (ट) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (ठ) "अन्तरण" के अन्तर्गत, धारा 3 के अधीन किसी स्थल या इमारत का विक्रय या पट्टे पर दिया जाना है ;
- (ड) "अन्तर्गति" से किसी फर्म या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के अधीन कोई स्थल या इमारत किसी भी रीति में चाहे जो भी हो, विक्रय की जाती है, पट्टे पर दी जाती है या अन्तरित की जाती है, और उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी इस के अन्तर्गत हैं ;
- (ढ) "नगरीय सम्पदा" से धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नगरीय सम्पदा के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;
- (ण) "कर्मशाला" से ऐसी इमारत या स्थान अभिप्रेत है, जिसमें या जिस के अहात में निम्नलिखित के लिए किसी प्रक्रिया की सहायता के लिए या उससे आनुषंगिक उपयोग में किसी शारीरिक श्रम का प्रयोग या उपयोग किया जाता है :—
- (i) किसी वस्तु या उसके भाग को बनाने में ,
- (ii) किसी वस्तु को परिवर्तित, मुरम्मत अथवा अलंकृत या परिष्कृत करने में ;
- (iii) किसी वस्तु को विक्री के लिए अनुकूलित करने में ।

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की या उस द्वारा अर्जित भूमि में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरीय सम्पदा घोषित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार नगरीय सम्पदा में राज्य सरकार की किसी भूमि या इमारत का, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसे वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए अधिरोपित करना उचित समझे, चाहे निलामी द्वारा, आवंटन द्वारा या अन्यथा विक्रय कर सकेगी, पट्टे पर दे सकेगी या अन्यथा अन्तरण कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किसी अन्तरण के लिए प्रतिकूल धन, राज्य सरकार, को, ऐसी रीति में, ऐसी किस्तों में और ब्याज की ऐसी दर पर, जैसी विहित की जाए, सन्दत्त किया जाएगा।

(4) उप-धारा (2) के अधीन किसी स्थल या इमारत के अन्तरण के कारण राज्य सरकार को दाय, ब्याज सहित प्रतिकूल धन का असदत्त भाग या कोई अन्य राशि, यदि कोई हो, यथास्थिति, उस स्थल या इमारत पर प्रथम प्रभार होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई अन्तरीति, सिवाय सम्पदा अधिकारी की पूर्वलिखित अनुज्ञा के, उप-धारा (2) के अधीन उस को अन्तरित स्थल या इमारत में किसी अधिकार, हक और हित को विक्रय करने, बंधक करने या अन्यथा (सिवाय मासानुमास पट्टे के तौर पर) अन्तरण करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह रकम, जो इस उप-धारा के अधीन प्रथम प्रभार है, राज्य सरकार को पूर्णतः सन्दत्त नहीं कर दी गई हो।

4. (1) राज्य सरकार या मुख्य प्रशासक, नगरीय सम्पदा के उचित आयोजन या विकास के प्रयोजन के लिए किसी स्थल या इमारत की बाबत या तो साधारण तथा सम्पूर्ण नगरीय सम्पदा के लिए या उसके किसी विशेष परिक्षेत्र के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषयों के बारे में ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसे आवश्यक समझे जाएं, अर्थात्:—

(क) किसी इमारत की ऊंचाई या अग्रभाग का स्थापत्य आकार;

(ख) वियोजित या अर्ध-वियोजित इमारतों अथवा दोनों का परिनिर्माण और ऐसी इमारतों से अनुलग्न भूमि का क्षेत्र;

(ग) आवासिक इमारतों की संख्या जो किसी परिक्षेत्र में किसी स्थल पर परिनिर्मित की जा सकेंगी;

(घ) दुकानों, कर्मशालाओं, भाण्डागारों, कारखानों या विनिर्दिष्ट स्थापत्य आकार की इमारतों या किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजनों के लिए परिकल्पित इमारतों के परिनिर्माण के बारे में प्रतिशेद;

(ङ) दिवारों, बाड़ों, झाड़वन्दी या किसी अन्य संरचनात्मक या स्थापत्य निर्माण की ऊंचाई और अवस्थिति का अनुरक्षण;

(च) इमारतों के परिनिर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिए स्थलों के उपयोग के बारे में निर्बन्धन।

क्षेत्रों की  
नगरीय  
सम्पदाएं  
घोषित करने  
और नगरीय  
सम्पदाओं में  
भूमि और  
इमारतों के  
अन्तरण के  
बारे में  
राज्य सर-  
कार की  
शक्ति।

इमारतों के  
परिनिर्माण  
के बारे में  
निर्देश जारी  
करने की  
शक्ति। -

(2) प्रत्येक अन्तरीति, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करेगा और, यथासंभव शीघ्रता के साथ, किसी इमारत को परिनिर्मित करेगा या ऐसे अन्य कदम उठाएगा जो ऐसे अनुदेशों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

इमारत  
नियमों के  
उल्लंघन में  
इमारत के  
परिनिर्माण  
का वर्जन ।

5. (1) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (2) के अधीन बनाए गए किन्हीं इमारत नियमों के उल्लंघन में, किसी नगरीय सम्पदा में किसी इमारत का परिनिर्माण या अधिभोग नहीं करेगा ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इमारतों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) इमारत के बाह्य और विभाजन दीवारों, छतों, फर्शों, सीढ़ियों, लिफ्टों, अंगीठियों, चिमनियों और अन्य भागों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी अवस्थिति या स्थान निर्धारण अथवा निर्माण का ढंग ;
- (ख) आवासिक या पाकशाला के प्रयोजनों के उपयोग के लिए आशयित किसी इमारत की छतों और फर्शों की ऊंचाई और ढलान ;
- (ग) वायु के अवाध परिसंचरण या आग के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए किसी इमारत या उसके भाग में संवातन या उभमें छोड़ा जाने वाला स्थान ;
- (घ) किसी इमारत की मंजिलों की संख्या और ऊंचाई ;
- (ङ) किसी इमारत में प्रवेश करने या उससे बाहर जाने के लिए साधनों का प्रबन्ध करना ;
- (च) बैठकों, शयन कक्षों या पशुओं के उपयोग के लिए आशयित कमरों की लम्बाई, चौड़ाई ;
- (छ) कमरों का संवातन, कमरों, इमारत की बाह्य दीवारों के बाहरी भागों से परे प्रक्षेपण के और दरवाजों या खिड़कियों की अवस्थिति और लम्बाई, चौड़ाई ;
- (ज) इमारतों के परिनिर्माण, पूर्ण करने और अधिभोग के उचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय ;
- (झ) इमारत के रेखांकों, संशोधित रेखांकों और समाप्ति रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में आवश्यक और आनुषंगिक प्रमाण-पत्र ।

इमारतों के  
स्थल को  
उचित अनु-  
रक्षण की  
अपेक्षा करने  
की शक्ति ।

6. यदि मुख्य प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या इमारत की दशा या उसका प्रयोग, किसी नगरीय सम्पदा के किसी भाग की उचित योजना या, उसी सुख-पुविधाओं अथवा वहां जन साधारण के हितों पर, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो वह उस स्थल या इमारत के अन्तरीति या अधिभोगी पर ऐसे पग उठाने, और ऐसी अवधि के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए और तत्पश्चात् उसे यथा विनिर्दिष्ट रीति में अपना अनुरक्षण करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील कर सकेगा ।

7. (1) नगरीय सम्पदा में किसी सुख-सुविधा की व्यवस्था, अनुरक्षण या उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, किसी स्थल या इमारत के वार में उसके अन्तरीति या अधिभोगी पर ऐसी फीस और कर (जो तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्राह्य किसी फीस या कर के अतिरिक्त होगा) जो वह आवश्यक समझे उद्गृहीत कर सकेगी।

सुख-सुविधाओं के लिए कर या फीस का उद्ग्रहण।

(2) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती हो, कि अन्तरीति या अधिभोगी एक धार्मिक या पूर्य संस्था है अथवा वह उस सुख-सुविधा का उपभोग नहीं करता है जिसके लिए कोई फीस या कर उद्गृहीत किया जाता है, तो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्तरीतियों या अधिभोगियों के किसी वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीसों और करों के संदाय से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकेगी।

8. (1) मुख्य प्रशासक, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी नगरीय सम्पदा या उसके किसी भाग में, मार को प्रभावित न करने वाले अनुकूलनों और परिवर्तनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के सभी या किन्हीं उपबन्धों को, जहां तक ऐसे उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत नहीं हैं, लागू कर सकेगा।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के कुछ उपबन्धों को नगरीय सम्पदा में लागू करने की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने पर, मुख्य प्रशासक यथा-स्थिति नगरीय सम्पदा या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, ऐसी अधिसूचना द्वारा लागू किए गए उपबन्धों के अधीन उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और उन्हीं कृत्यों का पालन करेगा जो ऐसी नगरपालिका या इस का प्रधान अथवा कार्यकारी अधिकारी या समिति या कोई अन्य कृत्यकारी प्रयोग और पालन करता, यदि नगरीय सम्पदा प्रथम श्रेणी की नगरपालिका होती।

(3) उप-धारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी सम्पदा को यथा लागू हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए या कृत्यों का पालन करते हुए, मुख्य प्रशासक, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन होगा और आयुक्त या उपायुक्त के नहीं।

(4) राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के किन्हीं उपबन्धों का लोप कर सकेगी या उसमें उस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों को जोड़ सकेगी और तदुपरि अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(5) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी की जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हों, रखी जाएगी। यदि उस सत्र के, जिसमें यह इस प्रकार रखी जाती है या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगी। किन्तु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात को विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शास्ति का  
अधिशोपण  
और बकाया  
की वसूली  
का ढंग।

9. (1) जहाँ कोई अन्तरीति धारा 3 के अधीन किसी स्थल या इमारत के अन्तरण के कारण किसी अन्य राशि या किसी प्रतिफल धन या उसकी किस्त के अथवा किसी पट्टा के बारे में देय किसी लगान के सन्दाय में कोई व्यतिक्रम करता है, या जहाँ कोई अन्तरीति या अधिशोगी, धारा 7 के अधीन उदगृहीत किसी फौस या कर के सन्दाय में कोई व्यतिक्रम करता है, वहाँ सम्पदा अधिकारी निदेश दे सकेगा कि, बकाया की रकम के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक रकम, जो उस द्वारा अवधारित की जाएगी, यथास्थिति अन्तरीति या अधिशोगी से, शास्ति के रूप में वसूल की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन संदेय राशि के सन्दाय में किसी व्यतिक्रम की दशा में, व्यतिक्रम में परादेय रकम उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के रूप में संदत्त की जाने के लिए निदेशित, यथास्थिति, किसी अन्य रकम सहित, यदि कोई हो, अन्तरीति या अधिशोगी से, उसी रीति में भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

अन्तरण की  
शर्तों को भंग  
करने के  
लिए सम-  
पहरण।

10. धारा 3 के अधीन किसी स्थल या इमारत के अन्तरण के कारण प्रतिफल धन या उसकी किसी किस्त या ऐसे किसी स्थल या इमारत के पट्टे के बारे में संदेय किसी लगान के सन्दाय के मामले अथवा ऐसे अन्तरण की किन्हीं अन्य शर्तों के भंग की दशा में, सम्पदा अधिकारी, यदि वह ठीक समझे, इस प्रकार अन्तरीति स्थल या इमारतों की पुनरग्रहण कर सकेगा और आगे उस के बारे में संदत्त सम्पूर्ण धन, या उसके किसी भाग को, यदि कोई हो, समपहृत कर सकेगा।

अपील और  
पुनरीक्षण।

11. (1) धारा 9 या धारा 10 के अधिन सम्पदा अधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर, ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए, मुख्य प्रशासक को अपील कर सकेगा :

परन्तु मुख्य प्रशासक, यदि उस का समाधान हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त हेतुक द्वारा समय के भीतर अपील फाइल करने से निवारित रहा था, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) मुख्य प्रशासक, अपील की सुनवाई के पश्चात्, अपीलाधीन आदेश को पुष्ट फेरफार या उल्ट सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) मुख्य प्रशासक, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त कोई आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख मंगवा सकेगा जिनमें सम्पदा अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है और उनके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे :

परन्तु मुख्य प्रशासक इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश उसको सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं करेगा।

(4) जहाँ कोई व्यक्ति उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन मामले का विनिश्चय करते हुए मुख्य प्रशासक के किसी आदेश द्वारा व्यथित हो, वहाँ वह, ऐसे विनिश्चय की उमे संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिए लिखित आवेदन कर सकेगा, और राज्य सरकार मुख्य प्रशासक के विनिश्चय को पुष्ट, परिवर्तित या विरुद्धित कर सकेगी।



12. यदि मुख्य प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि नगरीय सम्पदा में साधारणतया वृक्षों का या किसी विनिर्दिष्ट किस्म के पेड़ों का परिरक्षण या रोपण आवश्यक या समीचीन है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया वृक्षों या ऐसे किस्म के वृक्षों के बारे में जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसा आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् वृक्ष परिरक्षण आदेश कहा गया है) कर सकेगा, और ऐसा आदेश निम्नलिखित को विनियमित, निर्वन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा—

- (क) सिवाय मुख्य प्रशासक की पूर्व अनुज्ञा से, वृक्षों का कटान, शीर्षकटन, छंटाई या जानबूझ कर नष्ट करना; और
- (ख) उसमें किसी स्थल या स्थान में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्हीं वृक्षों या वृक्षों की किस्मों का रोपण और पुनरोपण।

13. यदि मुख्य प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि किसी नगरीय सम्पदा में विज्ञापनों के संप्रदर्शन को प्रतिषिद्ध या विनियमित करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, विज्ञापनों के संप्रदर्शन को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए आदेश (जिस इसमें इसके पश्चात् विज्ञापन नियन्त्रण आदेश कहा गया है) कर सकेगा और ऐसा आदेश निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगा :—

- (क) उन विज्ञापनों के आकार, रूप और स्थिति जिन्हें संप्रदर्शित किया जा सकेगा; वे स्थल जिन पर ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किए जा सकेंगे, और वह रीति जिसमें इनको भूमि या इमारत पर चिपकाया जाना है को विनियमित करने के लिए;
- (ख) विज्ञापन के संप्रदर्शन के लिए मुख्य प्रशासक की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने के लिए;
- (ग) किसी विज्ञापन जिसे आदेश के उल्लंघन में संप्रदर्शित किया जा रहा है, को हटाने या विज्ञापनों के संप्रदर्शन के उपयोग के लिए किसी स्थल जिसे उस प्रयोजन के लिए आदेश के उल्लंघन में उपयोग किया जा रहा है को रोकने की अपेक्षा करने को मुख्य प्रशासक को समर्थ बनाने के लिए;
- (घ) आदेश में विनिर्दिष्ट स्थानों में विज्ञापनों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस के लिए।

14. कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उप-धारा (2) या धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहा साबित होता है, बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। निदेश आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति।

15. (1) यदि कोई व्यक्ति वृक्ष परिरक्षण आदेश या विज्ञापन नियन्त्रण आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जो कोई उक्त आदेशों में से किसी एक के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात् उक्त उपबन्धों का उल्लंघन जारी रखता है, पश्चात्पूर्ति दोषसिद्धि पर, पूर्वोक्त जुर्माने से और अतिरिक्त जुर्माने से जो पूर्व दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् जारी उल्लंघन के प्रत्येक दिन के लिए बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। वृक्ष परिरक्षण आदेश और विज्ञापन नियन्त्रण आदेश और उल्लंघन के लिए शास्ति।

(2) न्यायालय, उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित करते समय निदेश दे सकेगा कि विज्ञापन के लिए प्रयुक्त कोई वृक्ष या उसका कोई भाग अथवा कोई सामग्री, जो कि उल्लंघन का विषय है, राज्य सरकार को समपहृत की जायेगी या उसके मूल्य के समतुल्य रकम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

नियमों को  
भंग करने  
के लिए  
शास्ति।

16. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का कोई उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा; और न्यायालय किसी नियम के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति के दोषसिद्धि पर दण्डादेश पारित करते समय, निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पत्ति या उसका भाग, जिसके बारे में नियम का उल्लंघन किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत की जाएगी।

दृष्टांत.—जहाँ अप्राधिकृत संरचना का निर्माण किया गया है या किसी अप्राधिकृत रीति में किसी स्थल पर कोई घृणाजनक सामग्री या पदार्थ संगृहीत किया गया अथवा ढेर लगाया गया है या जहाँ विज्ञापन नियन्त्रण आदेश के उल्लंघन में कोई विज्ञापन बोर्ड स्थापित किया गया है वहाँ ऐसी संरचना, सामग्री, पदार्थ या बोर्ड समपहरण के लिए दायी होगा, ना कि वह स्थल या इमारत जिस पर वह अवस्थित या स्थिर किया जाए :

परन्तु यदि कोई इमारत, इमारत नियमों के उल्लंघन में आरम्भ, परिनिर्मित या पुनःपरिनिर्मित की जाती है, तो मुख्य प्रशासक, यथास्थिति, इसके आरम्भ किये जाने या पूर्ण किए जाने के छः मास के भीतर इसके स्वामी को लिखित नोटिस तामील करवा कर, इमारत को परिवर्तित या गिराने की अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगा। ऐसे नोटिस में वह अवधि भी विनिर्दिष्ट की जायेगी जिसके दौरान ऐसा परिवर्तन या गिराना पूरा किया जाता है और, यदि नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो मुख्य प्रशासक उक्त इमारत को स्वामी के खर्चे पर गिराने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु यह और कि मुख्य प्रशासक, ऐसी किसी इमारत के परिवर्तन या गिराए जाने की अपेक्षा करने की बजाए, शमन के रूप में ऐसी रकम, जैसी वह युक्तियुक्त समझे, स्वीकार कर सकेगा।

वास्तुविदों,  
अभियन्ताओं  
और नल-  
साजों का  
रजिस्ट्रीकरण  
और अनु-  
ज्ञापन।

17. कोई भी वास्तुविद या अभियन्ता जिसकी विहित अर्हताएं नहीं हैं सम्यक् रूप से अर्हित नहीं समझा जाएगा और सम्यक् रूप से अर्हित वास्तुविद या अभियन्ता अथवा नलसाज से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति जब तक कि मुख्य प्रशासक द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञापित न हो यथास्थिति किसी रेखांक या इमारत को सम्पूर्ति प्रमाणित करने या किसी नलसाजी के काम में रखे जाने के लिए सक्षम नहीं होगा।

इमारतों या  
भूमि में  
प्रवेश करने  
की शक्तियां।

18. मुख्य प्रशासक, अधिभोगी को या, यदि कोई अधिभोगी न हो, तो किसी इमारत या भूमि के स्वामी को चौबीस घण्टे का नोटिस देने के पश्चात्, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय किसी व्यक्ति को, निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा—

(क) किसी इमारत या भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण के लिए और उसका तलमापन या माप लेने के लिए; या

(ख) किसी इमारत में या निर्माणाधीन संघर्षों की परीक्षा करने अथवा मलनालियों या नालियों का मार्ग अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि में प्रवेश करने के लिए ; या

(ग) किसी इमारत या किसी भूमि पर, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई इमारत, मंजूरी के बिना या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दी गई किसी मंजूरी के उल्लंघन में परिनिमित्त या पुनःनिमित्त की जा रही है, या की गई है, और ऐसे माप लेने के लिए और ऐसे कोई अन्य कार्य करने जो प्रवेश करने के लिए आवश्यक हों ।

19. कोई भी न्यायालय, मुख्य प्रशासक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के परिवाद पर या उसके द्वारा सूचना दिए जाने के सिवाय, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अभियोजन के लिए प्रक्रिया ।

20. राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा, इन अधिनियम के अधीन या उस द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, किया गया कोई आदेश या दिया गया निदेश किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

न्यायालयों की अभिकारिता का वर्जन ।

21. (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, निदेशों या आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही मुख्य प्रशासक, सम्पदा अधिकारी या उनके निर्देशन के अधीन कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, निदेशों या आदेशों के अनुसरण में कारित या सम्भावितः कारित किसी नुकसान के बारे में कोई बाद या अन्य विधिक, कार्यवाही राज्य सरकार, मुख्य प्रशासक, सम्पदा अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

22. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा प्रयोज्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी । जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

प्रत्यायोजन ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मुख्य प्रशासक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को अपने अधीनस्थ ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

23. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) वे निबन्धन और शर्तें जिन पर इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि या इमारत अन्तर्गत की जा सकेगी ;

- (ख) वह रीति जिसमें किसी अन्तरण के लिए प्रतिफल धन संदत्त किया जा सकेगा ;
- (ग) संदेय ब्याज की दर, और इस अधिनियम के अधीन संदेय किस्तों, ब्याज, फीस, किराया या अन्य देयों के संदाय के लिए प्रक्रिया ;
- (घ) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन किसी स्थल या इमारत में किसी अधिकार, हक या हित का अन्तरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;
- (ङ) किसी इमारत का परिनिर्माण या किसी स्थल का उपयोग ;
- (च) धारा 7 के अधीन फीसों या करों का उदग्रहण ;
- (छ) वे निबन्धन और शर्तें जिनको भंग करने के लिए किसी स्थल या इमारत को पुनःग्रहण किया जा सकेगा ;
- (ज) इस अधिनियम के अधीन अन्तर्गत स्थलों पर पुनर्परिनिर्मित की जाने वाली इमारतों के बारे में शर्तें ;
- (झ) नोटिस का प्रारूप और रीति जिसमें नोटिसों की तामील की जा सकेगी ;
- (ञ) वह प्रारूप और रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपीलें और आवेदन दाखिल किए जा सकेंगे और ऐसी अपीलों और आवेदनों पर उदग्रहण फीस ;
- (ट) धारा 5 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विषय ; और
- (ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाये तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवमान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और  
व्यावृत्तियाँ ।

24. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दी पंजाब इस्टेट (डिवेलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1964 एतद्वारा निरसित किया जाता है :

(1966 का  
31)  
(1964 का  
22)

परन्तु एतद्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचना या प्रारम्भ की गई या जारी रखी गई कार्यवाहियाँ भी हैं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

(धारा 8 देखें)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धाराएं 90 से 92, 103, 104, 105, 107 से 109, 119 से 123, 124 से 130, 140 से 149, 150, 151 से 159, 164 से 170, 181, 188, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222, 223, 224, 225, 226; 227, 228 से 238, 239, 240 से 242, 243 से 245, 247, 249, 251, 254 और 255 के उपबन्ध।

